and effect devolution of powers and decentralisation of authority. For this purpose, the Government intends to pursue a two track policy. On the first track, the recommendations of the Sarkaria Commission on which there is already a broad consensus, will be implemented through legislation and administrative action as appropriate. On the second track, the Government proposes to appoint a High Level Committee to review and update the recommendations of the Sarkaria Commission and look into the vital question of devolution of financial powers from the Central Government to the State Governments.

Division of Delhi into Nine Districts

417. SHRI O.P. KOHL1: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the proposals from the Government of Delhi to carve out nine Districts and 27 Sub-Divisions have been pending with the Ministry for long time;

(b) if so, since when and the steps taken to clear the same; and

(c) whether the decentralisation of the vast administrative structure likely to take at the door steps of the people of Delhi besides benefiting them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) In order to decentralise the administrative structure of National Capital Territory of Delhi, a proposal to create nine districts is in an advanced stage of consideration. The proposal in its present form was received from the Government of National Capital Territory of Delhi in 1994. The objective of decentralisation is, inter-alia, to provide a compact and manageable district, to provide the common citizen a ready access to the administration for redressal of his grievances and to make the administration more responsive.

Hotline Connection with Kremlin

418. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a hotline is proposed to be set up between the Kremlin and the Prime Minister's Office in New Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for a hot-line was agreed during the visit of Russian Prime Minister, Victor Chernomyrdin, to India in December, 1994. The technical parameters of the proposed hot-line will be a dedicated and secure telephone link between the offices of the Prime Minister of India and the President of the Russian Federation.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वस्त्र मिलें

419. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी वस्त्र मिलें पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार बंद पड़ी मिलों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश स्थित मिलों को पुनः चालू करने के लिए कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा): (क) मै॰ अजंता टेक्सटाइल लि॰ उत्तर प्रदेश की दिनांक 1.10.95 से बंद पड़ी होने की रिपोर्ट मिली। मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष से कोई मिल बंद पड़ी होने की रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजना बनाने तथा उन्हें स्वीकृत करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Accident Prone Zone in Andhra Pradesh

420. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the most accident prone zone in Andhra Pradesh in the Aluru Tadepalli-gudum segment of the National Highways;

(o) whether any monitoring has been done of this accident prone sector; and

(c) if so, the derails thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATARAMAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात सरकार की वस्त्र उत्पादन संबंधी परियोजनाएं

421. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई वस्त्र उत्पादन संबंधी परियोजनाएं अब भी केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्य को परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब के कारण कितना वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई वस्त्र उत्पादन संबंधी कोई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायगढ़ जिला डाकघर में अंतिम भुगतान हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या

422. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायगढ़ जिला डाकघर में नवम्बर, 1995 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंतिम भुगतान के लिए कितने मामले लंबित पड़े थे;

(ख) कितने मामले छह माह से अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों में तत्काल भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभाग द्वारा जमाकर्ताओं को समय पर पूरी राशि का भुगतान करने में क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) महोदय, नवम्बर, 1995 तक रायगढ़ जिला डाकघर में बचत योजनाओं के अंतर्गत केवल 600 मामले अंतिम भुगतान के लिए लंबित है।

इन महीने से अधिक अवधि का कोई भी मामला अंतिम भुगतान के लिए लंबित नहीं है।

(ग) इन मामलों में भुगतान करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं।

(घ) विगत समय में डाकघर के कार्य में वृद्धि हुई है परन्तु जो अतिरिक्त कार्य बढ़ा है उसके अनुपात में स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अंतिम भुगतान के लंबित मामले कर्मचारियों को मानदेय देकर निपटाए जा रहे है।

जल का उपयोग

423. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में औसतन वार्षिक, 1,170 एम०एम० वर्षा के माध्यम से जल की उपलब्धि होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में इस जल की बहुत कम मात्रा का ही उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें से सिंचाई, उद्योगों और पीने के लिए कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार शेष जल के उपयोग के लिए क्या योजना आरंभ करने का विचार रखती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्रा): (क) जी हां